(a) whether the Oil and Natural Gas Commission has informed his Ministry of the advice of the Institute of Reservoir Studies to close down one fourth of the oil wells in Bombay High and the Gandhar field because of very high gas oil ratio;

(b) if so, what are the reasons for this State of affairs;

(c) whether his Ministry have given the go-ahead signed to the ONGC to rectify the wells in order to effect the necessary pressure balance and reduce the oil-gas ratio; and

(d) to what extent oil production will be affected thereby and the steps being taken/proposed to be taken to meet the shortfall?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) to (c) The regulation of production of oil and gas from reservoirs is a dynamic and normal reservoir management practice to attain reservoir withdrawal balance with pressure maintenance to optimise oil recovery. Closure of wells/ strings is an integral part of such reservoir management practices. The Institute of Reservoir Studies of ONGC studies the parametres of reservoir management in the reservoirs of ONGC and makes reports from time to time which have also been sent to Government. Such reservoir management is part of ONGC's normal operations and they do not require go-ahead from the Government. In respect of the management of Bombay High reservoirs Government had appointed a committee under the Chairmanship of Shri A. B. Dasgupta, former Chairman, Oil India Limited which has submitted its report in November, 1990. This report is under examination in consultation with ONGC.

(d) The extent by which oil production would be affected as a result of the measures required to be taken would be known only after a final decision on the recommendations of the Dasgupta committee has been taken.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि

222. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अजीत सिंह झरोड़ा :
श्री चतुरानन मिश्र :
कुमारी सरोज खापर्डे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की दरों में भारी वृद्धि किये जाने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस वृद्धि के विरुद्ध आम जनता में भारी रोष है ;

(घ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष उठाये गये घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(च) इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धाकने) : (क) से (घ) अप्रैल, 1985 में टैरिफ में विगत के संशोधन के बाद से विद्युत की उत्पादन लागत/क्रय मूल्य समेत विभिन्न निवेशों की लागत में समग्र रूप से वृद्धि होने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भारी मात्रा में राजस्व की हानि हो रही है । अपनी व्यवहारिक वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1 मार्च, 1991 से अपनी विद्युत टैरिफ में संशोधन करने का निर्णय

लिया है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा टैरिफ में संशोधन किए जाने के विरुद्ध जनता-जनार्दन से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । इनको दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भेज दिया गया है । दिल्ली के लिए टैरिफ का निर्धारण करना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ।

(ङ) और (च) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की टैरिफ मितव्ययी न होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान इसको निम्नानुसार राजस्व की हानियां हुई :—

वर्ष	हानि (करोड़ रु० में)
1987-88	178.62
1988-89	179.99
1989-90	233.29

इन हानियों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उठाए गए कदमों में 1 मार्च, 1991 से टैरिफ में संशोधन करना, क्रेसेडर्स प्रतिष्ठापित किए जाने सहित पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कटौती करना, विद्युत की चोरी को नियंत्रित करना तथा प्रचालनात्मक व्यय का समुचित रूप से नियंत्रण करना आदि शामिल है ।

—

PAPERS LAID ON THE TABLE

[The Deputy Chairman in the chair].

THE DEPUTY CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, a very serious situation has arisen..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete the 'Papers to be laid' Business.

I. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Vadodara and related papers.

II. Statements showing the action by Government on the various assurances, promises and undertakings given during the various Sessions.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): I lay on the Table:—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Twenty-first Annual Report and Accounts of the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Vadodara, for the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

II. Statements (in English and Hindi) showing the action taken by Government on the various assurances, promises and undertakings given during the Session shown against each:—

(1) Statement No. XXIV—Hundred and Thirty-seventh Session, 1986.

(2) Statement No. XXVIII—Hundred and Fortieth Session, 1987.

(3) Statement No. XXV—Hundred and Forty-second Session, 1987.

(4) Statement No. XXIII—Hundred and Forthy-third Session, 1987.